>

Title : Regarding issue of capitation fee for Graduate and Post-graduate courses in Medical Sciences.

डा. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : महोदया, पिछले दिनों से बहुत सारे स्कैम्स इस देश में उजागर हुए हैं, लेकिन मैडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में स्थिति भयावह है। वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट सीट एक करोड़ से दो करोड़ रूपए तक नीलाम हो रही है। यह एक-दो स्थानों पर नहीं है अनेक कॉलेजों और अनेक संस्थाओं में ऐसी ही स्थिति है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सब संस्थाएं अधिकांश प्राइवेट हैं। ऐसा लगता है कि मैडिकल चिकित्सा में जो विस्तार होना चाहिए वह नहीं हुआ है। मेरे सामने ये आंकड़े हैं कि अगर हमारे देश में 100 ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें से सिर्फ 29 छात्र ही पोस्ट ग्रेजुएट बन पाते हैं। इस तरह से बहुत कम स्थान पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए 9085 स्थान क्लिनिकल कोर्सेज में है, 662 स्थान प्री क्लिनिकल पाठ्यक्रम में हैं। 1303 स्थान पैरा क्लिनिकल पाठ्यक्रम में है। हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए यह बहुत कम है और ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में मैडिकल चिकित्सा में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। दूसरा पक्ष यह है कि अगर आज सीट एक करोड़, दो करोड़ रूपए में बिकेगी तो केवल धनी-मानी लोग, कालाबाजारी लोग ही अपने बच्चों को वहां भेज सकेंगे। गरीब आदमी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट हो पाना मुश्किल है। उसके लिए तो ग्रेजुएट होना भी मुश्किल है क्योंकि उसमें भी 12, 20, 25 लाख रूपए की बोली लगकर सीट दी जाती है। इसमें आम आदमी कैसे पढ़ पाएगा, वह कैसे चिकित्सक बन पाएगा, और वह स्पेशलिस्ट तो बन ही नहीं सकेगा। देश में जिस मात्रा में चिकित्सकों की कमी है उसे हम कैसे पूरा करेंगे। महामहिम, राष्ट्रपति महोदया ने चिकित्सा सुविधा के विस्तार के बारे में बातें कही हैं। हमारे सरकारी पक्ष ने आम आदमी के लिए चिकित्सा सुलभ कराने की बात कही है। जब चिकित्सक ही नहीं होंगे तो चिकित्सा कहां से सुलभ होगी? जब आप यहां चिकित्सा की पढ़ाई की सुविधा नही देंगे तो लोग बाहर चले जाएंगे।

मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आज इस देश में प्रतिवर्ष सिर्फ 80 डॉक्टर ही पोस्ट ग्रेजुएट कॉर्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अमेरिका में 800 बनते हैं और इन 800 में अधिकांश भारतीय हैं। यानी भारत के कॉर्डियोलॉजिस्ट यहां न रहकर विदेशों में जा रहे हैं और हमारे यहां दिल के मरीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर की चिकित्सा के अभाव में मरते जा रहे हैं। यह परिस्थिति क्यों है? मैडिकल काउंसिल और चिकित्सा के विस्तार के बारे में क्या सरकार कुछ विचार करेगी?[r6] क्या कोई रैगूलेटरी एथॉरिटी बनेगी? क्या ये फीसें निरन्तर बढ़ती चली जानी चाहिए? क्या गरीब आदमी के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या आम आदमी को इलाज के लिए कोई स्पैशलाइजेशन नहीं मिलना चाहिए? हमारे संविधान का निदेश है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार करेगी। मैं नहीं जानता कि कितने सरकारी महाविद्यालय चिकित्सा के क्षेत्र में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने खोले हैं? क्यों नहीं खोले हैं और क्या वजूहात हैं? कहीं तो नीति में गड़बड़ी है? कहीं न कहीं हमने रैगूलेटरी एथॉरिटी के मामले में कोई चिंता नहीं की है? कहीं न कहीं हमने मेडिकल चिकित्सा के बारे में कोई चिंता नहीं की है?

महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही स्थिति पहले इंजीनियरिंग में हुआ करती थी। मुझे सौभाग्य मिला उस क्षेत्र के लिए काम करने का। हमने उसमें विस्तार किया और आज इंजीनियरिंग और आईटी में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो रही है। लेकिन चिकित्सा में क्यों पैदा हो रही है? यह एक गंभीर विषय है, देश के स्वास्थ्य के लिए, देश के गरीब आदमी के लिए और खास तौर पर पूरी शिक्षा के व्यापारीकरण पर एक सवाल है। कमिर्शियलाइजेशन आफ एजूकेशन का यह एक ज्वलंत उदाहरण है। मैं यह समझता हूं कि कोई भी सरकार, जो कि आम जनता को चिकित्सा और शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार देने की बात करती है, वह इस स्थिति को कैसे सहन कर सकती है?

महोदया, मेरे पास छात्र और उनके अभिभावक इस संबंध में आते हैं, लेकिन जब मैं मालूम करता हूं तो पता लगता है कि पोस्ट ग्रेजूएट कोर्सिज़ में सीटों की संख्या बहुत कम है और प्रवेश नहीं मिल सकता है। सरकारी विद्यालय भी बहुत कम हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह पहले ऐसी स्थिति का निर्माण करे, जिससे मेडिकल कोर्सिज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन की संख्या बढ़े, साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएशन की संख्या भी बढ़े। केवल 32 हजार मेडिकल ग्रेजुएट्स एक साल में इस देश में पैदा होते हैं। एक अरब बीस करोड़ की जनसंख्या के लिए हम किस मात्रा में चिकित्सक देश को दे रहे हैं? इसके बाद भी हम आशा करते हैं कि इस देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा और हम इक्कीसवीं शताब्दी में जा सकेंगे? दूसरी तरफ यही बच्चे विदेशों में जाकर नाम कमा रहे हैं।

इसलिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। सरकार को इस पर एक कप्रीहेंसिव पालिसी लेकर सदन के सामने आना चाहिए और यह आश्वासन देना चाहिए कि वे लोग जो एक-दो करोड़ में नीलामियां कर रहे हैं, वे लोग जो आपकी सरकार में भी शामिल हैं, उनके बारे में शंकाएं जाहिर की गई हैं और आरोप लगाए गए हैं कि उनके विद्यालयों में भी बीस-बीस लाख रूपये की कैपीटेशन फीस ली जाती है। यह कहां तक उचित है, ऐसे सभी लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। कैपीटेशन फीस बिलकुल बंद होनी चाहिए। सरकारी महाविद्यालयों की संख्या बढ़नी चाहिए। इस स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? इस पर एक कप्रेहेंसिव प्लान सदन के सामने आना चाहिए।

महोदया, इस समय मुझे न तो स्वास्थ्य मंत्री और न ही शिक्षा मंत्री दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वे इस बारे में सदन के सामने जल्दी से जल्दी पूरी नीति की घोषणा करें। इस कैपीटेशन फीस को तत्काल रूकवाएं और मैरिट के आधार पर गरीब बच्चों को आगे आने की व्यवस्था करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।